gas in Cauvery, we have found gas in Krishna and Godavari, and if the Southern gas grid is created, it will link all the four Southern States and avoid wastage of this precious national resource. Therefore, I would like to know from the Minister because now we are having some continuity—he also hails from the South—as to what is the present position of a Southern gas grid.

SHRI S. KRISHNA KUMAR: Sir, as regards the first part of the hon. Member's supplementary, gas flaring, of course, is a national waste. But we have a time-bound programme including a Rs. 7,500 crore World Bank project by which we hope to achieve zero-gas flaring or otherwise...

SHRI MURASOLI MARAN: By when?

SHRI S. KRISHNA KUMAR: ... Avoid this phenomenon in the next four to five years.

As regards the second part of the question, the need for a Southern gas grid or let us say National gas grid has been voiced from many quarters. An Inter-Ministerial Committee is looking into the whole issue and its feasibility. They have been given certain terms of reference, and their Report is awaited.

MR. CHAIRMAN: Question No. 2.

Purchase of Westland helicopters

*2. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 944 given in the Rajya Sabha on 29th July, 1991 and state:

(a) the number alongwith the year of purchase of each Westland Helicopter Corporation of India Limited; and

(b) what is the amount of foreign exchange involved in their purchase?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI M.O.H. FAROOK): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The contract for purchase of 21 Westland W-30 helicopters was signed in March, 1986. The helicopters were received in India as per following details:—

Year	No. of helicopters received
1986	5
1987	12
1988	4
Total	21

(b) The Foreign Exchange cost of acquisition of 21 helicopters, spare engines, ground support equipment and engine test bed was £ 70 million equivalent to Rs. 141.53 crores. Of this, £ 65 million (Rs. 130.91 crores) was covered by an ODA Grant.

श्री कृष्ण लाल शर्मा : सभापति जी, इस प्रश्न पर कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है । राज्य सभा में भी पहले यह प्रश्न उठाया जा चुका है । मंत्रीजी ने जवाब भी दिया है, किन्तु लगता यह है कि इस सवाल को रहस्यमय तरीके से, इसका उत्तर ठीक तरीके से न देकर, छिपाने की कोशिश की जा रही है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस प्रश्न के माध्यम से जो मैं पूछ रहा हूं उसका स्पष्ट उत्तर दें और जो आशंकायें लोगों में इस सवाल पर पैदा हो गयी हैं, उनका समाधान करने के लिए पूरे तथ्य सदन के सामने रखें ।

महोदय, मेरा इसमें पहला पूरक प्रश्न यह है कि (क) क्या यह सच है कि तीन एक्सपर्ट कमेटीज ने यह रिपोर्ट दी थी कि यह हैलीकाप्टर्स न खरीदें जाएं । इसके बाद भी सरकार ने यह हैलीकाप्टर्स खरीदे । अगर यह रिपोर्ट के बावजूद

खरीदे हैं जो कि विपरीत रिपोर्ट थी कि यह न खरीदे जायें तो इसमें सरकार को क्या व्यवस्था थी ? यह मेरे पहले प्रश्न का (क) भाग है और (ख) भाग यह है कि क्या हम हैलीकाप्टर्स को बनाने वाली जो वैस्ट लैन्ड कम्पनी है उसकी क्या यह स्थिति थी कि यह कंपनी दिवालियापन के कगार पर थी, उसको बचाने के लिए और यू० के० के प्रैशर में हमारी सरकार ने यह हैलीकाप्टर्स खरीदने स्वीकार कर लिए ? मेरे पहले पूरक प्रश्न का भाग (ग) यह है कि क्या हमने राजनीतिक स्तर पर या अन्य किसी स्तर पर किसी मिडिल मैन को लाभ पहुंचाने के लिए यह सारी ढील की है ? इसके अंदर हम लोगों ने किसके हित को ध्यान में रखकर यह सारी ढील की है ? मैंने इस पहले पूरक प्रश्न में तीन बातें पूछी हैं इनका मंत्री महोदय जवाब दें तो मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा ।

SHRI M. O. H. FAROOK: Sir, in this transaction, the whole thing is a grant. The British Government has given 70 million pounds equivalent to Rs. 141.53 crores as grant.

MR. CHAIRMAN: Is it grant or loan?

SHRI M. O. H. FAROOK: It is all grant. It is 65 million pound grant.

MR. CHAIRMAN: So, our cost is only 5 million.

SHRI M. O. H. FAROOK: Yes. Our cost is 5 million. Afterwards, when they found that there is some defect in operation they gave 10 million more as grant for operation. So, there is no question of ourselves having paid.

MR. CHAIRMAN: You have not paid any money?

SHRI M. O. H. FAROOK: No, Sir.

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : महोदय, मैं आपके पहले प्रश्न के बारे में कहना चाहूंगा कि कुछ एक्सपर्ट कमेटीज नियुक्त की गयी थी और उन्होंने भी इसका आंकलन किया । उनकी भी रिपोर्ट पेश की गयी । उसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा जायजा लिया और यह तय किया गया कि यह वैस्ट लैंड हैलीकाप्टर्स के लिए क्योंकि 65 मिलियन पाउंड्स जैसा कि मंत्री महोदय बता चुके हैं, आउटराइट ग्रांट्स के रूप में मिल रहा है, उसके अलावा 10 मिलियन पाउंड्स और आपरेशन एक्सपेंसेस के लिए मिल रहा है। और कोई भी हमारी तरफ से खर्चा नहीं होगी, मात्र 5 मिलियन पाउंड्स का खर्चा होगा, इसलिए तय किया गया कि टैक्नो इकोनोमिक ग्राउंड्स पर इस हैलीकाप्टर्स को खरीदा जाए माने लिया जाय ।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Sir, the case is...

MR. CHAIRMAN: No, Mr. Gurupadaswamy...

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I am not asking question. I just want to draw his attention... (*Interruptions*).

श्री कृष्ण लाल शर्मा : महोदय, मैं मंत्री महोदय से अपना दूसरा पूरक प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि क्या कारण है कि तीन एक्सीडेंट्स हुए । एक वैष्णो देवी में हुआ, फिर एक नर्थ ईस्ट में हुआ और एक जुहू में बंबई में हुआ, लेकिन पवन हंस लिमिटेड ने इसको बार बार आपरेट करने की कोशिश की । आखिर, यह रिस्क क्यों ली गयी य-जानते हुए भी कि यह हैलीकाप्टर्स काम नहीं कर रहे हैं और इस तरह के तीन सीरियस एक्सीडेंट्स होने के बावजूद पवन हंस लिमिटेड को किस की डायरेक्सन थी, क्या गवर्नमेंट की थी, किस की थी ?

इसका "क" । दूसरा "ख" यह है कि अब इसके फाइनल डिस्पोजल के बारे में गवर्नमेंट ने क्या सोचा है ? यह जो 21 हैलीकाप्टर ग्राउण्ड हो गए और सरकार

ने कह दिया कि फाइनली, वी हैव टेकन ए डिसिजन कि भाई, ग्राउंड हो गए हैं, तो इसको फाइनली क्या डिस्पोज आफ कर रहे हैं या रीसेल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं ? एक यह प्रश्न है । फिर "ग" यह है कि क्या इसके कारण से, आपने तो कह दिया कि उनकी ग्रांट से हमको मिले हैं, क्या हमें और कुछ लोसेस इन्कर करने पड़े ? जैसे यह हैलीकोप्टर हम उपयोग करने वाले थ ओ० एन० जी० सी० के आपरेशन के लिए और यह हैलीकोप्टर हम नहीं दे सके ओ०एन०जी० सी० को और उनकी और एक्सपेन्सेजस इन्कार करने पड़े । इसके बावजूद दूसरे देशों से और इमिडिएट, अर्जेन्ट कुछ रिक्वायरमेंट रखे., इस डील के कारण से यद्यपि यह डील, जैसा आपने कहा ग्रांट से हल हो गया है । लेकिन, इसकी वजह से क्या और कुछ लोसेस इन्कर करने पड़े हैं ? अगर करने पड़ हैं तो कितने है ? इसकी जानकारी भी दी जाए ।

श्री सभापति : अब, और उसके आगे तो नहीं है ? "घ" "ड" तो नहीं है ?

श्री हरण लाल शर्मा : नहीं, बस इतना है ।

SHRI M. O. H. FAROOK: It it true that there have been three accidents; one in August 1988, another in February 1989 and the third in December 1989. The specific clause of this grant is that this helicopter has to be purchased from them only, and this was the specific clause for grant for this specific helicopter. Therefore, we had no other option... (*Interruption*).

श्री सभापति : यह कह रहे हैं, दान की गाय के दांत नहीं देखे जाते ।

श्री प्रमोद महाजन : कोई मृत्यु दान में दे दे तो वह स्वीकार थोड़े ही हो सकता है ।

श्री सभापति : अरे भाई, दान तो यह स्वीकार कर ही लेना चाहिए । मृत्यु हो तो मृत्यु ही सही ।

SHRI M. O. H. FAROOK: In view of the defects which have been found, we are thinking of disposing of these helicopters and various ways and means are being found by the Ministry.

श्री हरण लाल शर्मा : सर, आपने यह नहीं बताया कि एक्सीडेंट होने के बाद इसको दुबारा आपरेट करने की एफर्टस क्यों की गई ?

श्री माधवराव सिंधिया : सर, कुछ जो दुघटनायें हुई, उसमें से एक आपरेटर एरर के कारण हुई, पहली दुघटना जुलाई 1988 में आपरेटर एरर के कारण हुई थी और उसके बाद टैक्नीकली फाल्टस के कारण भी दो दुर्घटनायें हुई । इस बीच दिसंबर, 1989 में हुसैनी कमैटी नियुक्त की गई कि पूरी तरह से जांच करे कि इसमें क्या तकनीकी खामी है, क्या कमी है या हमारी मैंटिनेन्स की कोई समस्या है, प्रोब्लम है । तो हुसैनी कमैटी ने अपनी रिपोर्ट शायद अप्रैल, 1990 में दी थी और तब तक यह एयर-क्राफ्ट खड़े रहे थ। उसके बाद कुछ मोडिफिकेशन के भी सुझाव रख गए कि इसमें कुछ इंजिन और टैक्नीकल स्पेसिफिकेशन में भी कुछ मोडिफिकेशन करें । तो चर्चायें चल रही थीं वैस्टर्न के साथ । इस बीच फिर स एक और एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद हमन ग्राउन्ड किया ।

SHRI SURESH KALMADI: I had warned many times on the floor of this House against the purchase of Westland helicopters. Even at that time I had said that even if you are getting these helicopters free, please don't touch them.

I would like to know whether the Westland company has honoured all its commitments which were made to the Indian Government at that time. I would further like to know as to what has been the outflow in foreign exchange on account of spares and maintenance which the Indian Government had to bear till date. I would also like to know whether because of

these accidents, which I hear are due to engines failing, or whatever, they sent a team, or whether they have been shirking their responsibility, and in that case whether the Indian Government is going to take any legal action against the company. The hon. Minister said that they are going to dispose of the helicopters. I would like to know whether they are going to call for global tenders or how they are going to dispose them of, or whether they are selling it as scrap.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: With regard to foreign exchange outflow till date, I will have to get full details and send it to the hon. Member.

SHRI SURESH KALMADI: It is a very big amount and I am surprised to note that the Ministers were not properly briefed by the officer and the amount of foreign exchange which has gone into this is more than the cost of the aircraft.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: What was your first question? Do you want to know how are we going to dispose them of?

SHRI SURESH KALMADI: My most important question is about the commitment.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: As far as the commitment is concerned, the commitment was for the supply of 21 helicopters. That commitment was fulfilled. The second commitment was for an extra grant of 10 million pounds. That commitment was also fulfilled. Subsequently, the technical defects were noticed and the Hussaini Committee also came up with certain recommendations for modifications. As far as the technical parameters are concerned, I must admit that Westland took a long time about it. Not only the Westland but Rolls Royce also took a very long time about it. Since the crash took place, we grounded the whole thing and we have decided not to operate it, in any case.

SHRI SURESH KALMADI: Are you taking legal action against Westland? We have paid a fabulous amount. It is a camouflage.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: We can take legal action only under the terms of the agreement. Under the terms of the agreement, it is unlikely that we have grounds for legal action. The third question which the hon. Member asked was What are we going to do in the future? We are examining various options and soon we would be taking a decision and we would be putting it up to the Cabinet.

SHRI SURESH KALMADI: Are you going to sell it as scrap by weight?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: The Minister of State has made a very astounding remark that the Government of India had to get these helicopters because there was no other option. I marked these words. Please look into the records. I have written here what he said. Then the Minister said that these helicopters were supplied under grant and a large element of grant was there. My question is whether these gamts—it may be aid or it may be grant—should be utilised in such a reckless manner without looking into the project itself. These helicopters have been purchased under an agreement between the Government of India and the Government of U.K. At that time , there was a lot of presssure exerted on the Government of India by the U.K. The then Prime Minister —I do not want to mention her name—exerted all pressures on the Government of India to purchase these helicopters. At that time, the Government of India did not look into the whole thing regarding the technical feasibility and the technical aspects of these helicopters. As a result, we have incurred a heavy loss. The oil sector itself was using those helicopters and we suffered a lot on account of these helicopters. Now, all the helicopters have been grounded. My second question is whether the Government

of India should not have exercised control over the utilisation of grant. It may be a grant but it is still money. This grant may have been utilised for some other purpose.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Let me first correct the impression of the hon. Member. I do not know if my hon. Minister of State used the word 'no other option'. If he did, he obviously meant there may have been other options but this was an outright grant. We were not spending any money at all except the 5 million pounds that we were going to spend on some spares. Apart from that, we are not spending any money. I think, in that context, what the Minister meant when he used the words 'no option' was not that other alternatives were not available to us, but then the outflow would have been much later. As far as what the hon. Member asked about the alleged reckless use of the grant is concerned, there were two committees which went into this and did clear it on technical parameters and also the economic parameters Whatever the differentiation there was on the economic parameters of operation, that was compensated by the 10 million pounds that was given again as an outright grant against operational loss. Therefore, there were two Committees which had cleared this helicopter subsequently.

श्री मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में बताया कि यह हमें बाहर से अनुदान के तौर पर मिला था । लेकिन यह भी पवन हंस के लिए लायबिलिटीज बना है । जो फोरेन एक्सचेंज दिया गया था वैस्टलैंड खरीदने के लिए उसके लिए पवन हंस को काफी इक्विवेलेंट डिपोजिट करना पड़ा गवर्नमेंट के एकाउंट में और वह पूरा नहीं कर पाये, उसके लिए ब्याज भरना पड़ रहा है जिसके कारण पवन हंस खुद-ब-खुद सूखा जा रहा है, मरा जा रहा है । मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि उन्होंने पार्टी के जवाब में यह कहा है कि—

"The foreign exchange cost of acquisition of 21 helicopters, spare engines, ground support equipment and engine test bed was 70 million pounds equivalent to Rs. 141.53 crores."

जो ओरिजिनल कान्ट्रेक्ट था उसके मुताबिक इनीशियल रेंकेज ऑफ स्पेयर्स तमाम के साथ दिये, लेकिन उस वक्त जो एंटीसिपेट किया गया था स्पेयर्स के लिए उसके बावजूद बाद में यह देखा गया कि यह स्पेयर्स काफी नहीं है । इतनी टैक्नीकल स्नैग्स हो रही है और ग्राउंडिंग करना पड़ रहा है, तो बाद में और भी स्पेयर्स खरीदने पड़े । उसके लिए जो फारेन एक्सचेंज एमाउंट खर्च करना पड़ा वह कितना था और किस के अनुपात से मिला था और यह सिर्फ जो प्राइम सप्लायर्स हैं, मैन्यूफैक्चरर्स हैं उनसे खरीदा गया या बीच में मिडिलमैन थे तो वह कौन मिडिलमैन थे?

श्री माधव राव सिंधिया : सर, ब्याज का तो सवाल ही नहीं उठता । अभी आउट राइट गारंटी था तो ब्याज का तो सवाल ही नहीं उठता । जो पूरा एमाउंट आया 65 मिलियन पौंड का और 10 मिलियन पौंड आपरेशनल लोस के एगेंस्ट, वह तो आउट राइट गारंटी था, उस पर कोई ब्याज तो था नहीं । जहां तक स्पेयर्स का सवाल है, आनरेबिल मेंबर कलमाडी साहब ने भी यह बात पूछी थी, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स जो भी अभी तक आउट फ्लो हुआ है, हर एक डिटेल्स मैं मेम्बर्स को देने के लिए तैयार हूं अगर वह चाहते हैं ।

Coal supply to power plants in Madhya Pradesh

*3. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State of Madhya Pradesh is not be-